वी.बी. राजू

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

4 सितंबर, 1980

[वाई.वी.चंद्रचूड़,सी.जे., एस.मुर्तजा फजल अली और ए.डी.कौशल, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 217 और 222(2) – दायरा - किसी राज्य के पुनर्गठन पर किसी अन्य उच्च न्यायालय को आवंटित न्यायाधीश-ऐसा आवंटन यदि यह एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बराबर है।

बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम की धारा 29(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने यह निर्धारित किया था कि अपीलकर्ता जो उस समय बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश था, उसे उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहना चाहिए और नवगठित गुजरात के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी याचिका में अपीलकर्ता ने दावा किया कि एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति का स्रोत संविधान के अनुच्छेद 217(1)(सी) के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 222 में है, हालांकि आक्षेपित आदेश का तात्पर्य यही है बॉम्बे

पुनर्गठन अधिनियम की धारा 29(1) के तहत पारित किया गया है, जो एक न्यायाधीश के स्थानांतरण के आदेश के समान है और इसलिए, वह अनुच्छेद 222(2) द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक भत्ते का हकदार था।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि धारा 29 के तहत पारित आदेश तत्कालीन बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दो नए उच्च न्यायालयों में आवंटित करने का आदेश था और ऐसा आवंटन स्थानांतरण के समान नहीं है। अपील पर एक खंड पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 222 द्वारा परिकल्पित स्थानांतरण एक ऐसी स्थिति में स्थानांतरण था जब एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे मौजूदा उच्च न्यायालय में उन कारणों से भेजा गया था जिनका किसी राज्य के विभाजन या पुनर्गठन और एक नए उच्च न्यायालय की स्थापना से कोई लेना-देना नहीं था, जबकि धारा 29 उन प्रावधानों का हिस्सा थी जो गुजरात राज्य के गठन के पूरक, आकस्मिक या परिणामी थे।

याचिका खारिज करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: अनुच्छेद 222(2) के तहत प्रतिपूरक भत्ते की पात्रता न्यायाधीश के "स्थानांतरित" होने पर सशर्त है, अर्थात, अनुच्छेद 222(1) द्वारा परिकल्पित अनुसार स्थानांतरित किया गया है। चूंकि अपीलकर्ता को उस न्यायालय की स्थापना पर गुजरात उच्च न्यायालय में "आवंटित" किया गया था, इसलिए वह क्षतिपूर्ति भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं था। [617 डी]

संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 एक विशेष स्थिति से संबंधित हैं और जब तक संसद द्वारा घोषित कानून के प्रावधान को एक नए राज्य के गठन के लिए पूरक, आकस्मिक या परिणामी माना जा सकता है, तब तक यह लागू करने योग्य होगा, भले ही यह संविधान के कुछ प्रावधानों के संशोधन के बराबर हो। अधिनियम की धारा 29 में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से गुजरात राज्य के गठन और इसके लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए परिणामी है । उस उच्च न्यायालय की स्थापना के उद्देश्य से ही बंबई उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों को गुजरात उच्च न्यायालय में आवंटित किया गया था और हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति स्थानांतरण की कुछ विशेषताओं का हिस्सा हो सकती है। , उन्हें संविधान के अनुच्छेद 222(1) के अर्थ के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया गया कहा जा सकता है। [617 ए-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1134/1974

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए.संख्या 255/71 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 2-8-1973 से उत्पन्न।

अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से।

एल. जे. नैन और सुश्री ए. सुभाशिनी, प्रत्यार्थियों की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

कौशल, न्यायाधिपति. -

1. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1)(सी) के तहत दिए गए प्रमाण पत्र द्वारा यह अपील उसके दिनांक 2-8-1973 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है और इसमें निर्णय की आवश्यकता वाला एकमात्र बिंदु यह है कि क्या क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा बॉम्बे री-ऑर्गनाइजेशन एक्ट, 1960 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 29 की उप-धारा (1) के तहत एक आदेश पारित किया गया है और यह निर्धारित करना कि अपीलकर्ता 1 मई 1960 को बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहेगा और गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत स्थानांतरण के आदेश के रूप में माना जाएगा।

2. अपीलकर्ता को 29 जून, 1959 को बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अधिनियम लागू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने अपीलकर्ता के संबंध में अधिनियम की धारा 29(1) के तहत उक्त आदेश (इसके बाद आक्षेपित आदेश के रूप में संदर्भित) पारित किया, जो अभी भी बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश था। (और उस न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीश) ताकि 1 मई 1960 से अपीलकर्ता गुजरात उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बन जाए। यह दावा करते हुए कि विवादित आदेश संविधान के अनुच्छेद 222(1) के अर्थ में स्थानांतरण के आदेश के समान है, अपीलकर्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें प्रार्थना की गई कि भारत संघ और

गुजरात राज्य की सरकारों को निर्देशित किया जाए। उन्हें भत्ता देने के लिए, उनके अनुसार, वह अक्टूबर, 1963 से संविधान के अनुच्छेद 222(2) के तहत हकदार हो गए थे। याचिका में एक अन्य प्रार्थना भी की गई थी लेकिन अब हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि बाद में उसे वापस ले लिया गया।

3. गुजरात उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद की सराहना करने के लिए और फिर निर्णय पारित करने वाली खंड पीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील में अब अपील के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) और अनुच्छेद 222 के प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है।

"217 (1) उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के मामले में, जैसा कि अनुच्छेद 224 में प्रदान किया गया है, और किसी अन्य मामले में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे।

परन्तु-

(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्याययाला के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;

(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को, अंतरित किये जाने पर रिक्त हो जायेगा"

"222(1) राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

(2) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान, जिसके दौरान वह संविधान (पंद्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 के प्रारंभ के पश्चात, दुसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकरात्मत भत्ता, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब ततक ऐसा प्रतिकरात्मत भत्ता, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, प्राप्त करने का हकदार होगा।"

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की दलीलों के अनुसार एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति का एकमात्र स्रोत अनुच्छेद 222 था जिसे अनुच्छेद 217(1)(सी) के साथ पढ़ा गया था। और आक्षेपित आदेश, जो शक्ति के उस स्रोत से प्राप्त एक आदेश था, इसलिए, स्थानांतरण के एक आदेश की तरह था, भले ही यह अधिनियम की धारा 29(1) के तहत पारित किया गया था, जो इस प्रकार है:

"(1). बंबई उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो नियत दिन से ठीक पहले पद धारण कर रहे हैं, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, उस दिन बंबई में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और गुजरात के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसद में निहित शक्तियों के अनुसरण में पारित किया गया था। अनुच्छेद 3 अन्य बातों के साथ-साथ नए राज्यों के गठन का प्रावधान करता है। इसके खंड (ए) के तहत संसद कानून द्वारा किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक मौजूदा राज्यों या उनके हिस्सों को एकजुट करके या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 4(1) के तहत अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान शामिल होंगे जो ऐसे कानून के

प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और इसमें ऐसे पूरक, आकस्मिक और भी शामिल हो सकते हैं। परिणामी प्रावधान (संसद में और ऐसे कानून से प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के प्रावधानों सहित) जैसा कि संसद आवश्यक समझे। अनुच्छेद 4 के खंड (2) के तहत ऐसे किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि अधिनियम की धारा 29 के तहत एक आदेश दो नए उच्च न्यायालयों के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के "'आवंटन" का एक आदेश था और ऐसा आवंटन संविधान के अनुच्छेद 217(1)(सी) या 222(1) के अर्थ के भीतर स्थानांतरण के बराबर नहीं था। । इस मामले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया। लेटर्स पेटेंट अपील में डिवीजन बेंच की राय थी कि यद्यपि विवादित आदेश स्थानांतरण के आदेश की तरह था, लेकिन इसके द्वारा किया गया स्थानांतरण अनुच्छेद 222(1) द्वारा विचार किए गए से पूरी तरह से अलग प्रकार का था। हालाँकि, वास्तव में। अपील खारिज करने के कारण वही थे जिनके कारण विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका सफल नहीं हो सकी। डिवीजन बेंच के अनुसार अनुच्छेद 222 द्वारा परिकल्पित स्थानांतरण उस स्थिति में स्थानांतरण था जब एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य मौजूदा उच्च न्यायालय में उन कारणों से भेजा गया था जिनका राज्य के विभाजन या पुनर्गठन और स्थापना से कोई लेना-देना नहीं था।

परिणामस्वरूप एक नए उच्च न्यायालय का गठन, जबकि अधिनियम की धारा 29 उन प्रावधानों का हिस्सा थी जो गुजरात राज्य के गठन के लिए पूरक, आकस्मिक या परिणामी थे।

खंड पीठ के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि गुजरात सरकार ने अपीलकर्ता के साथ अपने पत्राचार के दौरान, गुजरात उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति को बॉम्बे उच्च न्यायालय से स्थानांतरण के रूप में माना था, जिस तथ्य से इंकार नहीं किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि इसका विवादित मामले पर कोई असर नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका में विवंध का कोई तर्क नहीं दिया गया था।

4. अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद हमें अपील में कोई सार नहीं मिला और मोटे तौर पर, ऐसा करने के हमारे कारण उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा दिए गए कारणों से मेल खाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 एक विशेष स्थिति से संबंधित हैं और जब तक संसद द्वारा प्रख्यापित कानून के प्रावधान को एक नए राज्य के गठन के लिए पूरक, आकस्मिक या परिणामी माना जा सकता है, तब तक यह लागू करने योग्य होगा, भले ही यह एक की राशि हो। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन. अधिनियम की धारा 29 में निहित प्रावधान गुजरात राज्य के गठन और इसके लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए

स्पष्ट रूप से परिणामी है। उस उच्च न्यायालय की स्थापना के उद्देश्य से ही बंबई उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों को, ऐसा कहा जा सकता है, गुजरात उच्च न्यायालय को "आवंटित" किया गया था; और यद्यपि गुजरात उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति स्थानांतरण की कुछ विशेषताओं का हिस्सा हो सकती है, हमें नहीं लगता कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 222 के अर्थ के भीतर बॉम्बे उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया कहा जा सकता है। अनुच्छेद 222(2) के तहत प्रतिपूरक भत्ते की पात्रता न्यायाधीश के "स्थानांतरित" होने पर सशर्त है, अर्थात स्थानांतरित किया गया है जैसा कि अनुच्छेद 222(1) द्वारा परिकल्पित है। चूंकि अपीलकर्ता को उस न्यायालय की स्थापना पर गुजरात उच्च न्यायालय को "आवंटित" किया गया था, इसलिए वह प्रतिपूरक भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

5. परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है लेकिनलागत के बारे में कोई आदेश न दें।

पीबीआर.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक **श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता** द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****